Officers as on 1 January, 1983 alongwith roster for SCs and STs candidates in the Department of Electronics ;

(b) the total number of Scientific Officers as on 1 January 1983 belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(c) whether it is a fact that Scheduled Castes and Scheduled Tribes representation in the Department of Electronics is not adequate as per Government policy ; and

(d) the Government's policy to fill the reserved posts as mentioned in part (a) above ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS (SHRI M.S. SANJEEVI RAO) : (a) (i) 145 (includes 5 officers on deputation from other Ministries/Departments)

(ii) Reservation for Scheduled Castes (SCs) Scheduled Tribes (STs) acco rding to rosrer :

	SC	ST	
	19	9	
(b)	SC	ST	Remarks
	4	1	(3 SCs and 1 ST officers left the Department during the previous year)

(c) and (d) Yes, Sir. However, to fill up the reserved vacancies, the Department follows the procedure laid down by Government. The short-fall at any one point of time is taken into account while filling up vacancies at subsequent points of time.

विभागीय परीक्षाओं के लिए हिन्दी माध्यम का विकल्प

7248. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपके अधीन मंत्रालय/विभाग और उसके सम्बन्ध कार्यालयों में 1982 में कितनी विभागीय परीक्षाएं ली गई;

(ख) क्या ऐसी विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी का विकल्प दिया गया था और यदि हां, तो कितनी परीक्षाओं में;

(ग) उपर्युक्त सभी विभागीय परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को हिन्दी माध्यम से बैठने की अनुमति कब से दी जाएगी; और

(घ) इस संबंध में समुचित व्यवस्था करने के संबंध में कदम उठाए जा रहे हैं;

उद्योग मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) :

(क) उद्योग मंत्रालय और इसके सम्बद्ध कार्यालयों में वर्ष 1982 में कोई ऐसी परीक्षा नहीं ली गई।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता।

Recognition to all India Federation of S.C./S.T. backward classes and Minorities Employees Welfare Associations

7249. SHRI HIRALAL R. PARMAR : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether All India Federation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Backward Classes and Minorities Emplyees Welfare Associations (Regd) New Delhi had been requesting Government since long for according recognition on the ground that the communities for which it is working are already recognised by the Constitution ;

(b) whether recognition is not being accorded to this Federation only on the plea that it is a caste based organisation although the socially and economically backward castes are classified in the Constitution into four categories i.e. (i) Scheduled Castes, (ii) Scheduled Tribes (iii) Backward Classes, and (iv) Minorities ;

(c) whether Government have recognised other Welfare Associations or Councils etc. of these Communities ;

(d) if so, the reasons for according recognition to these associations or councils etc. and the precise policy of the Government under which these have been recognised ; and

(e) if not, the reasons for not recognising this Federation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) Yes, Sir.

(b) and (e) As part of Government policy, however, any association of Government employees formed on the basis of any Caste, Tribe, or Religious denomination or any group or section of such caste, tribe or religious denomination is not recognised by the Government.

(c) and (d) Government have enlisted some outside voluntary welfare associations of Scheduled Castes and Scheduled Tribes only for the purpose of giving wider publicity to the reserved vacancies.

अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

7250. **श्री हरीश रावत :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिलों ताड़ीखेत में ब्रोन्ज फैक्ट्री के बन्द होने से वह "शून्य उद्योग" जिला घोषित हो जाने के कारण जिले को पुन: वर्गीकृत किया जाएगा; और

(ख) "शून्य उद्योग" जिलों के औद्योगीकरण के लिए अब तक केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी): (क) अल्मोड़ा जिले में निम्नलिखित बड़े और मझौले उद्योग हैं :—

1. कुमार ब्रोन्ज पाउडर, तारीखेत ।
2. सरस्वती वूलन मिल्स, चेलियानौला (रानीखेत) ।
3. अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड, माटेला ।

अतएव इस जिले को "उद्योग रहित जिलों" में शामिल नहीं किया गया है ।

(ख) सरकार "उद्योग रहित जिलों" में नए एकक स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृत हेतु, सर्वप्रथम अधिमानता दे रही है ।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सम्पदाओं का कार्यकरण

7251. **श्री हरीश रावत :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन औद्योगिक रूप से पिछड़े स्थानों के नाम क्या हैं जहां औद्योगिक सम्पदाएं हैं और वहां इस समय कितने उद्योग चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इन औद्योगिक सम्पदाओं की वर्तमान स्थापित व्यवस्था और प्रगति से संतुष्ट है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को उसके विकास के लिए दी जानी वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी : (क) से (ग) औद्योगिक बस्तियों का विषय मुख्यत: राज्य सरकारों से संबंधित है । उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के 38 पिछड़े जिलों में से 26 जिलों/क्षेत्रों में 34 औद्योगिक बस्तियों की व्यवस्था है । इनमें 770 एककों के कार्यकरण होने की सूचना है । ये हैं अल्मोड़ा, आजमगढ़, बहराइच, बाराबंकी, बांदा, बुलन्दशहर, बस्ती, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, जौनपुर, झांसी, ललितपुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, पीलीभीत, पौढ़ी गढ़वाल, रामपुर, रायबरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर और उन्नाव ।

अतएव, उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में औद्योगिक बस्तियों की प्रगति की गति संतोषप्रद समझी जाती है ।

अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में टंगस्टन एवं अन्य उपयोगी खनिज

7252. **श्री हरीश रावत :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कुछ स्थानों में भूगर्भ सर्वेक्षण के दौरान टंगस्टन एवं अन्य उपयोगी धातुओं के भण्डार पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये भण्डार कहां-कहां